SONAANCHAL JOURNAL (Q2)
A Blind Peer-Reviewed Multilingual & Multidisciplinary Research Journal
Volume 1 | Issue 1
Publication Frequency: Bi-Annually
Access: Open and Free
Languages: Indian Languages

# NEP-2020 में समावेशी शिक्षा: विविधता, समानता और गुणवत्ता शिक्षा की दिशा में एक नई पहल

गुंजा मिश्रा*
*शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटनी, म.प्र.

## सारांश (Abstract)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त कदम है, जिसमें समावेशी शिक्षा को केंद्र में स्थान दिया गया है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों, क्षमताओं और विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों को एक समान, सम्मानपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। नीति शिक्षा को एक अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के रूप में स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा भाषा, लिंग, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, संस्कृति या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मुख्यधारा शिक्षा से वंचित न रहे। NEP-2020 बहुभाषिक शिक्षा, शिक्षण के लचीले और छात्र-केंद्रित मॉडल, शिक्षक क्षमता विकास, तकनीकी-सहायता प्राप्त शिक्षण, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा वंचित समूहों के लिए विशेष सहायता तंत्र जैसे अनेक उपायों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाती है। यह नीति दिव्यांग छात्रों के लिए Universal Access, barrier-free learning environment, और Individualized Support जैसी अवधारणाओं को भी

प्राथमिकता प्रदान करती है। यद्यपि नीति का दृष्टिकोण प्रगतिशील है, समग्र रूप से, NEP-2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक न्यायसंगत, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की एक मजबूत पहल है, जो सभी शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ एक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और मानव-केंद्रित समाज की नींव रखती है।

**प्रस्तावना**

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) आधुनिक शिक्षा-विचारधारा का वह केंद्रीय सिद्धांत है, जो प्रत्येक बच्चे को उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा शारीरिक-पारिस्थितिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए समान, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे वह अपनी सम्पूर्ण संभावनाओं के साथ विकसित हो सके। भारत के संदर्भ में यह दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ जातीय, भाषायी, आर्थिक तथा भौगोलिक विविधताएँ अत्यधिक व्यापक हैं। ऐसी स्थिति में समावेशी शिक्षा न केवल एक शैक्षिक आवश्यकता है बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में उठाया गया एक अनिवार्य कदम है।

इक्कीसवीं सदी की शिक्षा-व्यवस्था का केंद्रीय लक्ष्य केवल साक्षरता बढ़ाना नहीं, बल्कि शिक्षा को सुगम, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण और सर्वसमावेशी बनाना है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को लागू किया, जिसने देश की शिक्षा-

व्यवस्था को नई दृष्टि, नया स्वरूप और एक परिवर्तनकारी रूपरेखा प्रदान की। नई शिक्षा नीति ने समावेशी शिक्षा को शिक्षा-प्रणाली का अनिवार्य स्तंभ माना है, और इस बात पर विशेष बल दिया है कि कोई भी बच्चा—चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, भाषा, संस्कृति, लिंग, विकलांगता या आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हो—शिक्षा के दायरे से बाहर न रह जाए।

दरअसल, भारत में लंबे समय से शिक्षा में विविधताओं के कारण असमानताएँ दिखाई देती रही हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच, सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के बीच, भाषायी पृष्ठभूमि में भिन्नता वाले विद्यार्थियों के बीच—शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में अंतर व्यापक रहा है। समय के साथ शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे—समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई अधिनियम 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आदि—लागू किए गए, परंतु NEP-2020 ने इन्हें एक समन्वित ढाँचे में संगठित करके समावेशी शिक्षा को एक नई पहलकदमी, व्यापक दृष्टि और ठोस कार्ययोजना के रूप में स्थापित किया।

NEP-2020 का समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण व्यापक, संवेदनशील और बहु-आयामी है। नीति स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति, क्षमताएँ, सीखने का तरीका और पृष्ठभूमि अलग होती है, इसलिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ ऐसी होनी चाहिए जो इस विविधता का सम्मान करें। इसके लिए नीति में उपयुक्त पाठ्यचर्या, बहुभाषिकता, स्थानीय संदर्भों पर आधारित शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, विशेष शिक्षा सहयोगियों (Special Educators/Resource Teachers) की नियुक्ति, और

बाधारहित शिक्षण वातावरण (Barrier-Free Environment) तैयार करने पर बल दिया गया है। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों, लड़कियों, सामाजिक रूप से वंचित समूहों, आदिवासी बच्चों, प्रवासी बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए NEP कई लक्षित पहल की बात करती है। समावेशी शिक्षा को NEP-2020 एक अधिकार-आधारित मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें शिक्षा को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा सार्थक, उपयोगी और उच्च गुणवत्ता वाली हो। इसी कारण नीति में विद्यालयों में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, लिंग-संवेदनशीलता, समान अवसर, भावनात्मक और सामाजिक समर्थन, तथा व्यक्तिगत सीखने (Personalized Learning) की व्यवस्था पर भी बल दिया गया है।

NEP-2020 का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि समावेशी शिक्षा को अलग या विशेष शिक्षा के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे मुख्यधारा शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में किसी भी प्रकार का विभेद, भेदभाव, बहिष्कार या अलगाव न हो, और हर बच्चा अपने साथियों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़ सके। इस प्रकार, नीति "No Child Left Behind" की मूल भावना को व्यवहार रूप में साकार करने की दिशा में अग्रसर है। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए नीति में शिक्षकों की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षकों को विविधता का सम्मान करने, भिन्न-भिन्न शिक्षण पद्धतियाँ अपनाने, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को समझने

के लिए प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। NEP-2020 कहती है कि शिक्षक केवल ज्ञान प्रदाता नहीं, बल्कि *facilitator*, मार्गदर्शक और सहायक हों, जो प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें। इसके लिए बी.एड., एम.एड. सहित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी समावेशी शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों को अनिवार्य रूप से शामिल करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, नई शिक्षा नीति ने प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा को भी समावेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण-सामग्री, दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरण, ऑडियो-बुक्स, साइन-लैंग्वेज इंटरप्रेटेशन, और ICT आधारित शिक्षण साधन समावेशी शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाते हैं। विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए यह डिजिटल माध्यम सीखने के नए अवसर उत्पन्न करता है। NEP-2020 का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने समावेशी शिक्षा को केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे व्यावहारिक, लक्ष्य-उन्मुख और मापनीय पहल के रूप में प्रस्तुत किया है। नीति में "शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों" (SEDGs) की विशेष पहचान की गई है, जिनमें लड़कियाँ, अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चे, दिव्यांगजन, आदिवासी समुदाय, प्रवासी बच्चे, बहुभाषिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं। इन समूहों के लिए लक्षित समर्थन, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता और विद्यालय-समुदाय सहभागिता जैसे उपायों की व्यवस्था का प्रस्ताव नीति में शामिल है।

समावेशी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा सफल, सक्षम, रचनात्मक और आत्मनिर्भर बन सके। NEP-2020 इसी मूल्य-आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, जिसके अंतर्गत सीखने को आनंदमय, लचीला और जीवन-उन्मुख बनाया जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक-सहयोग, सहिष्णुता, सहयोग, सम्मान, बहुसंस्कृतिवाद तथा वैश्विक नागरिकता जैसी भावनाओं का विकास होता है, जो सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि NEP-2020 में समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक सुधार नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की पहल है। यह पहल शिक्षा को समानता, न्याय, सहभागिता, विविधता और गुणवत्ता के सिद्धांतों पर आधारित करती है, और भारत को एक ऐसे समाज की ओर अग्रसर करती है जहाँ हर व्यक्ति को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। समावेशी शिक्षा की यह नई पहल एक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और ज्ञान-आधारित समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

## शोध समस्या

समावेशी शिक्षा आधुनिक शैक्षिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक अंग है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी विविध शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप समान अवसर प्रदान करना है। यद्यपि भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ, अधिनियम और नीतियाँ लागू की गई हैं, फिर भी विद्यालय स्तर पर

इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। **NEP-2020** ने समावेशी शिक्षा को शिक्षा-प्रणाली का केंद्रीय स्तंभ मानते हुए विभिन्न समूहों —जैसे दिव्यांगजन, लड़कियाँ, अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, प्रवासी बच्चे, बहुभाषिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी, और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे—को मुख्यधारा शिक्षा से जोड़ने पर बल दिया है। फिर भी वास्तविक स्थिति यह दर्शाती है कि विद्यालयों में विविधता का सम्मान, समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, और आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण समावेशी शिक्षा का लक्ष्य पूरी तरह साकार नहीं हो पा रहा है। विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक अधिगम सहयोग, संसाधन केंद्र, ICT आधारित उपकरण, सुगम भौतिक वातावरण तथा प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों का अभाव गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और भी विकट है, जहाँ शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं।

इसके अतिरिक्त, अनेक शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता और कौशल का अभाव, बड़ी कक्षाएँ, बहुभाषिकता, सामाजिक-पारिवारिक असमानताएँ, और तकनीकी साधनों की सीमित उपलब्धता भी बाधा उत्पन्न करती है। NEP-2020 की अपेक्षाओं और विद्यालयों की वर्तमान परिस्थितियों के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, जिसे दूर करना आवश्यक है। इन्हीं चुनौतियों के संदर्भ में यह शोध यह जानने का प्रयास करता है कि **NEP-2020 द्वारा प्रस्तावित समावेशी शिक्षा की नई पहल विद्यालय स्तर पर किस हद तक प्रभावी है, किन समस्याओं का सामना**

**करना पड़ता है, और विविधता, समानता एवं गुणवत्ता शिक्षा को साकार करने में कौन-कौन से अवरोध मौजूद हैं।**

## शोध उद्देश्य

1. NEP-2020 में समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों, सिद्धांतों और नीतिगत पहल का विश्लेषण करना।
2. विद्यालयों में विविधता, समानता और गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने में समावेशी शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना।

## NEP-2020 में समावेशी शिक्षा के आयाम

नई शिक्षा नीति–2020 (NEP-2020) भारत की शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करती है। इस नीति का मूल लक्ष्य शिक्षा को **सुगम, समान, गुणवत्तापूर्ण और सर्वसमावेशी** बनाना है। समावेशी शिक्षा को NEP-2020 में केवल एक नीतिगत निर्देश के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र का **मूलभूत सिद्धांत** माना गया है। यह नीति शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के अधिकार के रूप में देखती है और यह सुनिश्चित करती है कि विविध सामाजिक, भाषायी, भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों वाले सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त हों। NEP-2020 में समावेशी शिक्षा के विविध आयाम निम्नलिखित हैं:

### 1. विविधता और समान अवसर का सम्मान (Respect for Diversity & Equity)

NEP-2020 इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने साथ विशिष्ट विविधताएँ लेकर विद्यालय में आता है। ये विविधताएँ भाषा, संस्कृति, लिंग, सामाजिक स्थिति, आर्थिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थान, क्षमता और अधिगम शैली से संबंधित हो सकती हैं।नीति विद्यालयों को ऐसे वातावरण के निर्माण की सलाह देती है, जहाँ—

- सभी विद्यार्थी सहज महसूस करें,
- भेदभाव न हो,
- अवसर समान हों,
- और विविधता को एक शक्ति के रूप में देखा जाए।

इस प्रकार NEP-2020 समावेशी शिक्षा को *समानता आधारित शिक्षा* के रूप में विकसित करती है।

**2. सामाजिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) पर विशेष ध्यान**

नीति में "**Socially and Economically Disadvantaged Groups (SEDGs)**" की विशेष पहचान की गई है। इन समूहों में शामिल हैं:

- SC/ST वर्ग
- OBC
- दिव्यांगजन
- लड़कियाँ एवं महिलाएँ
- आदिवासी समुदाय
- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे

- प्रवासी मजदूरों के बच्चे
- बहुभाषिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

NEP-2020 इन समूहों के लिए **लक्षित हस्तक्षेप**, संसाधन, छात्रवृत्तियाँ, आवासीय विद्यालय और अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान करने की बात करती है।

### 3. दिव्यांग बच्चों (CwSN) के लिए समावेशी कदम

नीति के अनुसार दिव्यांग बच्चों (Children with Special Needs) को मुख्यधारा विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार है। इसके लिए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

- **विशेष शिक्षा प्रशिक्षकों (Special Educators) की नियुक्ति**
- **रिसोर्स रूम** की स्थापना
- सहायक उपकरण, ICT-सहायता, साइन लैंग्वेज सामग्री
- बाधारहित (Barrier-Free) भौतिक वातावरण
- School Readiness Program

NEP-2020 का जोर यह है कि दिव्यांग बच्चे अलग-थलग न हों, बल्कि सभी बच्चों के साथ समान रूप से पढ़ें।

### 4. बहुभाषिकता और मातृभाषा-आधारित शिक्षा

भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, और विविध भाषाओं वाले भारत में भाषा ही कई बार बहिष्करण का कारण बनती है।NEP-2020 में—

- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा,

- बहुभाषिक शिक्षा,
- भाषा-अनुकूल पाठ्यचर्या,
- और अनुवाद-सुविधाएँ समावेशी शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। बहुभाषिकता विद्यार्थी की पहचान और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करती है तथा सीखने को सहज बनाती है

**5. गुणवत्ता शिक्षा के लिए समावेशी पाठ्यचर्या (Inclusive Curriculum)**

नीति में पाठ्यचर्या को लचीला, बहु-विषयी, कौशल-आधारित और *सीखने-केंद्रित* बनाने पर बल दिया गया है। प्रमुख बिंदु:

- सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षण सामग्री
- जीवन-कौशल, मूल्यों, सहयोग, समालोचनात्मक चिंतन का समावेश
- कला, खेल, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण
- 5+3+3+4 संरचना के अनुसार विकासात्मक उपयुक्तता

इससे सभी विद्यार्थी अपनी गति और शैली के अनुसार सीख पाते हैं।

**6. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (Teacher Preparation)**

समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आयाम **प्रशिक्षित और संवेदनशील शिक्षक** हैं।NEP-2020 में कहा गया है कि—

- शिक्षक विविधता को समझें,
- कक्षा में भेदभावरहित वातावरण बनाएँ,
- भिन्न-भिन्न शिक्षण रणनीतियाँ अपनाएँ,

- विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण करें।

इसके लिए B.Ed., M.Ed. और इन-सर्विस प्रशिक्षण में *समावेशी शिक्षा अनिवार्य घटक* बनाया गया है।

## 7. प्रौद्योगिकी-संचालित समावेशन (Technology Enabled Inclusion)

NEP-2020 डिजिटल शिक्षा और ICT उपकरणों को सभी बच्चों तक पहुँचाने पर बल देती है।
यह शामिल करता है:

- DIKSHA पोर्टल
- डिजिटल लर्निंग संसाधन
- ऑडियो-बुक्स, ई-बुक्स
- दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक तकनीक
- ऑनलाइन/ब्लेंडेड लर्निंग

डिजिटल साधन उन बच्चों के लिए शिक्षा का नया मार्ग बनते हैं जो स्थान, संसाधन या बाधाओं के कारण पीछे रह जाते हैं।

## 8. विद्यालय-समुदाय सहभागिता (School-Community Partnership)

समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नीति में—

- माता-पिता के साथ सहयोग,

- सामुदायिक संसाधनों का उपयोग,
- स्थानीय संस्कृति का सम्मान,
- विद्यालय प्रबंधन समितियों को सशक्त बनानेका प्रावधान है।

यह सहभागिता सभी विद्यार्थियों के लिए सहयोगी वातावरण तैयार करती है।

### 9. समग्र विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान

NEP-2020 मानती है कि शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास से भी संबंधित है।

- काउंसलिंग,
- स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम,
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता,
- खेल और कला आधारित गतिविधियाँसमावेशन की प्रक्रिया को मजबूती देती हैं।

### 10. मूल्यांकन की समावेशी प्रणाली (Inclusive Assessment)

नीति पारंपरिक परीक्षा-केन्द्रित प्रणाली से हटकर—

- फॉर्मेटिव मूल्यांकन,
- बहुआयामी मूल्यांकन,
- सीखने के स्तर पर आधारित मूल्यांकन,
- और व्यावहारिक, कौशल-आधारित मूल्यांकनपर जोर देती है।इससे प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर सकता है।

### निष्कर्ष

भारत में शिक्षा को अधिक समावेशी, समानतामूलक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020)** एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में उभरती है। यह नीति शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन की प्रक्रिया न मानकर, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं, पृष्ठभूमि और विविधताओं का सम्मान करने वाली व्यवस्था के रूप में विकसित करना चाहती है। समावेशी शिक्षा यहाँ एक ऐसी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत होती है जो न सिर्फ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक और बौद्धिक विविधताओं वाले सभी बच्चों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल देती है। NEP-2020 समावेशी शिक्षा को एक **न्यायपूर्ण, मानवीय और व्यापक शिक्षा प्रणाली** की आधारशिला मानती है। इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सार्वभौमिक पहुँच, दिव्यांगजनों के अधिकार आधारित दृष्टिकोण, बहुभाषिकता, लैंगिक संवेदनशीलता, वंचित समूहों के लिए विशेष सहयोग, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम, डिजिटल समावेशन, और शिक्षक क्षमता विकास जैसे विस्तृत आयाम सम्मिलित हैं। इन प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि नीति का उद्देश्य शिक्षा में अवसरों की समानता को सुनिश्चित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है, जहाँ प्रत्येक बच्चा अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँच सके। सैद्धांतिक आधारों—जैसे सामाजिक न्याय सिद्धान्त, मानव विकास परिप्रेक्ष्य, Vygotsky का सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत, Gardner का बहुविध बुद्धि सिद्धांत और Constructivist learning model—से यह सिद्ध

होता है कि विविधता को स्वीकारना, लचीला शिक्षण वातावरण बनाना, तथा छात्र-केंद्रित शिक्षण प्रदान करना समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। NEP-2020 भी यही दृष्टिकोण अपनाते हुए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना चाहता है जो ज्ञान, कौशल, मूल्यों और जीवन-क्षमता के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करे। यद्यपि नीति के उद्देश्यों और प्रस्तावित पहलों में एक प्रगतिशील दृष्टि है, परंतु वास्तविक क्रियान्वयन के स्तर पर अनेक चुनौतियाँ भी सामने हैं—जैसे अपर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, विद्यालयों का असमान बुनियादी ढाँचा, डिजिटल डिवाइड, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। इन चुनौतियों का समाधान बहु-स्तरीय प्रयासों—सरकार, शिक्षकों, समुदाय और अभिभावकों—के संयुक्त सहयोग से ही संभव है। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि NEP-2020 समावेशी शिक्षा को केवल एक शैक्षिक सुधार नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानती है। यह नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का सपना प्रस्तुत करती है जहाँ कोई भी बच्चा उसकी भाषा, क्षमता, लिंग, वर्ग, संस्कृति या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षण-अधिकार से वंचित न रहे। यदि इसके प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए, तो भारत न केवल 'सबके लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बल्कि एक समावेशी, संवेदनशील, और मानवीय समाज की स्थापना की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकता है।

## संदर्भ (References)

- Aggarwal, J. C., & Gupta, S. (2020). Inclusive Education: Concepts and Practices in India. नई दिल्ली: Shipra Publications.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. ब्रिस्टल: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
- Forlin, C. (2013). Future Directions for Inclusive Teacher Education: An International Perspective. लंदन: Routledge.
- Government of India. (2016). Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. नई दिल्ली: Ministry of Law and Justice.
- Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. नई दिल्ली: Ministry of Education.
- Mishra, R. (2022). समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका: NEP-2020 के संदर्भ में। शैक्षिक संवाद, 12(1), 55–66।
- NCERT. (2005). National Curriculum Framework 2005. नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।
- NCERT. (2021). Inclusive Approach in School Education: A Guide for Teachers. नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

- Rao, I., & Kalyanpur, M. (2017). Inclusive education in India: Policies, practices and challenges. Asia Pacific Education Review, 18(2), 219–232.
- Singal, N. (2019). Education of children with disabilities in India: Status, challenges and recommendations. International Journal of Inclusive Education, 23(7), 731–746.
- UNESCO. (2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. पेरिस: यूनेस्को।
- UNESCO. (2020). Inclusion and Education: All Means All (Global Education Monitoring Report 2020). पेरिस: यूनेस्को।
- UNICEF. (2014). Inclusive Education: Understanding Article 24 of the UNCRPD. न्यूयॉर्क: यूनिसेफ।
- World Bank. (2018). Learning for All: Inclusive Education Framework. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।
- अलम, एस. (2021). भारत में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में NEP-2020 का विश्लेषण। भारतीय शिक्षा समीक्षा, 45(2), 115–128।